



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 27 अगस्त, 2011 / 5 भाद्रपद, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सरथ सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी 39 मील शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सरथ सिंह पुत्र श्री कांशी राम, निवासी 39 मील शाहपुर, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके लड़के अनमोल सुखवाल का जन्म दिनांक 25-9-2003 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-8-2011 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 18-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री उज्जल राम पुत्र श्री धनी राम, निवासी कनोल, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री उज्जल राम पुत्र श्री धनी राम, निवासी कनोल, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी पुत्री पुष्पा देवी का जन्म दिनांक 16-3-2007 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उसका जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 9-9-2011 को अदालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अतः मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मुल राज, निवासी झुलाड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मुल राज, निवासी झुलाड़, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके लड़के रितीश कुमार का जन्म दिनांक 19-3-2006 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री हेम राज, निवासी सिहालेपुरी, डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री हेम राज, निवासी सिहालेपुरी, डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी लड़की पलवी का जन्म दिनांक 10-9-2006 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को या इससे पूर्व हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी योल झरेड़, मौजा नरेटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी योल झरेड़, मौजा नरेटी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी लड़की नेहा चौधरी का जन्म दिनांक 7-9-1997 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी योल झरेड़, मौजा नरेटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रेशमा देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी योल झरेड़, मौजा नरेटी, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके लड़के विशाल चौधरी का जन्म दिनांक 2-1-2000 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री वलबीर सिंह पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लाम, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वलबीर सिंह पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लाम, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती टिको देवी की मृत्यु दिनांक 7-4-2009 को हुई थी लेकिन उसकी मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद अपील गुजरने कोई भी उजर/एतराज कावले समायत न होगा तथा मृत्यु तिथि दिनांक 7-4-2009 को दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री सफारी, निवासी कवोल, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री सफारी, निवासी कवोल, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके लड़के संजीव कुमार का जन्म दिनांक 15-7-2006 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अतः मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किए जाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री फौन्दू राम, निवासी सलवाना, मौजा बड़ज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम की दुरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री फौन्दू राम, निवासी सलवाना, मौजा बड़ज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम नकल परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण—पत्र में धर्म चन्द दुरुस्त है। परन्तु कागजात माल में राम सिंह दर्ज है। जो गलत है। अतः राम सिंह उपनाम धर्म चन्द दुरुस्त करने के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री जटू पुत्र श्री किरपा राम, निवासी महाल मुन्दला, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम की दुरुस्ती कागजात माल में करवाने बारे।

श्री जटू पुत्र श्री किरपा राम, निवासी महाल मुन्दला, मौजा लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि मेरा असली नाम चन्दू लाल पुत्र श्री किरपा राम है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा नाम जटू लिखा गया है। जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम की दुरुस्ती होने में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को प्रस्तुत कर सकता है। बाद में कोई भी एतराज प्रस्तुत न होगा।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी वासा (भनाला), तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी वासा (भनाला), तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी लड़की शालिनी का जन्म दिनांक 8-1-2005 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री जिगरी राम पुत्र श्री सोरमा राम, निवासी ववूनी, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जिगरी राम पुत्र श्री सोरमा राम, निवासी ववूनी, डाकघर वौह, तहसील शाहपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 15-3-1982 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री मनोहर लाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी वासा, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मनोहर लाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी वासा, डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी लड़की मधुवाला का जन्म दिनांक 7-7-2005 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव व डाकघर भनाला, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी माता मन्शा देवी की मृत्यु दिनांक 27-10-2009 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री जयकरण, निवासी नौराहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री जयकरण, निवासी नौराहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता जय करण पुत्र गुलाबु की मृत्यु दिनांक 28-4-1994 को हुई थी लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी सिहू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी सिहू, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पुत्र अदित्य राणा का जन्म दिनांक 3-6-2008 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 9-9-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री हेत राम पुत्र श्री शिव राम पुत्र श्री रामू गांव वतीउड़ा, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

श्री कानिया राम पुत्र श्री रामू पुत्र श्री मोतिया, गांव वतीउड़ा, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

उनवान मुकद्दमा : इन्तकाल मकफूद—उल—खवरी चक वतीउड़ा, इन्तकाल नम्बर 68, चक सतरवड़, इन्तकाल नम्बर 10 चक वडोग, इन्तकाल नम्बर 39.

इस कार्यालय में श्री हेत राम पुत्र श्री शिव राम पुत्र श्री रामू, ग्राम वतीउड़ा ने एक प्रार्थना—पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उनका चाचा श्री कानिया राम कई वर्षों से लापता है, जो आज दिन तक घर वापिस नहीं आया है और उनकी तमाम सम्पत्ति उपरोक्त वर्णित चको में स्थित है, को उनके पिता शिव राम व स्वयं ने सम्भाल कर स्वयं काश्त करते आ रहे। इस प्रकार 84—85 वर्षों से कानिया राम लापता है और कानिया राम की वरास्त मकफूद—उल—खवरी करके उनके नाम कर दिया जाए।

इस इशतहार द्वारा श्री कानिया राम व आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कानिया राम की भूमि इन्तकाल मकफूद—उल—खवरी चक वतीउड़ा इन्तकाल नम्बर 68 चक सतरवड़, इन्तकाल नम्बर 10 चक वडोग, इन्तकाल नम्बर 39 दर्ज कर अन्तिम निर्णय के लिए दिनांक 26—9—2011 को निश्चित की गई है। यदि कानिया राम कहीं जीवित हो तो उक्त तारीख को हमारे कार्यालय में वरवक्त 10.00 बजे असातन व वकालतन हाजर होकर अपना पक्ष/पैरवी करे अन्यथा लापता/मृत्यु मानकर इन्तकाल वारसान उपरोक्त के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 21—8—2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जुलियस केरकेटा पुत्र श्री गैबरियल, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री जुलियस केरकेटा पुत्र श्री गैबरियल, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सन्दीप केरकेटा जिसकी जन्मतिथि 10—5—1989 तथा पुत्री संगीता केरकेटा जिसकी की जन्मतिथि 18—8—1991 है, के नाम नगर पालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाए गए हैं। जिन्हें प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-9-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर सन्दीप केरकेटा व संगीता केरकेटा के नाम एवं जन्मतिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी शिवा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी शिवा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री समीक्षा की जन्मतिथि 17-3-2008 है, का नाम ग्राम पंचायत शिवा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-9-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 समीक्षा का नाम एवं जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश, निवासी ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री वेद प्रकाश, निवासी ज्वालापुर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत

करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्रियों 1. कु0 मोनिका, 2. किरन जिनकी जन्म तिथियां 1. 9-12-1991, 2. 24-1-1995 है, के नाम ग्राम पंचायत अजौली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थन अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-9-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 मोनिका व किरन के नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री बाबू राम पुत्र श्री बाल किशन, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री बाबू राम पुत्र श्री बाल किशन, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री भावना कुमारी की जन्मतिथि 12-6-1998 है, का नाम ग्राम पंचायत कोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 19-9-2011 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 भावना का नाम एवं जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

वी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 20/2011 Date of Institution : 8-8-2011 Date of decision : Pending for 12-9-2011

Shri Daulat Ram son of Shri Bhagat Ram, resident of Village Hada Chadiyar, Post Office Chandi, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Daulat Ram son of Shri Bhagat Ram, resident of Village Hada Chadiyar, Post Office Chandi, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Miss. Sunita Devi born on 16-10-1998 at Hada Chadiyar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Chandi, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Miss. Sunita Devi daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 12-9-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 8th day of August, 2011.

Seal.

LALIT SHARMA,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.*

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 22/2011 Date of Institution : 9-8-2011 Date of decision : Pending for 12-9-2011

Shri Dharamvir son of Late Shri chhajju Ram Gupta, resident of New Elingim Lodge, Cart Road, Shimla-3, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Dharamvir son of Late Shri chhajju Ram Gupta, resident of New Elingim Lodge, Cart Road, Shimla-3, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his mother Smt. Kaushlaya Devi died on 29-5-1984 at Village Dhar-ki Ber, Subathu Road, Dharampur,

Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of death could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's death record, Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of Smt. Kaushlaya Devi mother of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 12-9-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 9th day of August, 2011.

Seal.

LALIT SHARMA,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.*

In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 5/IX/2011

Date of decision : Pending for 2-9-2011

Shri Mahender Dutt son of Shri Gauri Shankar, resident of Village and P. O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

1. (i) S/Sh. Narender Nath, (ii) Naresh Kumar, (iii) Uttam Chand, (iv) Vijay Kumar sons and (v) Smt. Asha Devi widow of Late Shri Maya Dutt.
2. Sh. Mani Ram son of late Shri Kalu, all resident of Vill. Deeb, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh,
3. Shri Dev Dutt son of Sh. Sehaj Ram,
4. Sh. Om Prakash son of Shri Sehaj Ram, all resident of Vill. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
5. Sh. Darli Dutt son of Sh. Tara Dutt,
6. Sh. Khem Chand son of Sh. Tara Dutt,
7. Smt. Leela Wati widow of Sh. Tara Dutt, all resident of Vill Bheron-ki-Ser, P. O. and Tehsil Kalka, District Panchkula (Haryana),
8. Sh. Laxmi Dutt son of Late Sh. Mathu Ram,
9. Sh. Durga Dutt son of late Shri Mathu Ram both resident of Village Garkhal Gaon, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
10. (a) Sh. Prem Dutt son, (b) Smt. Lajya Devi & (c) Smt. Bimla Devi daughters of late Shri Jagdish, all resident of Village Datyar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

11. (a) S/Sh. Bala Dutt, (b) Ganga Ram, (c) Puran Chand and (d) Naresh Kumar sons of late Shri mathu Ram son of Shri Dhani Ram, all resident of Vill. Deeb, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
12. (a) S/Sh. Durga Dutt & (b) Ruttan Chand sons of late Siri Ram, all resident of Vill. Patiana, P. O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
13. (a) Sh. Sukh Dev son of late Sh. Krishnia, resident of Vill. Patiana, P. O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh, (b) Sh. Deep Ram son of late Sh. Krishnia, resident of Vill. Gail, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
14. Shri Bhawani Dutt son of late Sh. Shiv Dayal.
15. Sh. Dina Nath son of late Sh. Shiv Dayal, all resident of vill. Deeb, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
16. (a) Sh. Hari Dutt son of late Sh. Shiv Ram, (b) Sh. Tula Ram son of late Sh. Shiv Ram, all resident of Village Deeb, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
17. Smt. Punni Devi daughter of late Sh. Anant Ram, resident of vill. Garkhal Gaon, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
18. (a) Sh. Jagdish son of late Smt. Shakuntala Devi, (b) Shri Ramesh son of late Smt. Shakuntla Devi, (c) Sh. Dinesh son of late Smt. Shakuntla Devi, (d) Smt. Urvashi daughter of late Smt. Shakuntla Devi, all resident of Village Garkhal Gaon, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
19. Smt. Bhago Devi daughter of late Sh. Anant Ram
20. Smt. Maya Devi daughter of late Sh. Anant Ram, all residents of Vill. Garkhal Gaon, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
21. Shri Lalit Mohan son of Sh. Radha Krishan
22. Smt. Gulab Devi wife of Sh. Radha Krishan, all residents of village and P. O. Bohli, Tehsil Kasauli, District solan, Himachal Pradesh.
23. Sh. Krishan Dutt son of Shri Maheshwara Nand
24. Smt. Kadshi daughter of Sh. Maheshwara Nand, all resident of village Garkhal Gaon, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
25. Sh. Prem Dutt son of Sh. Tulsi Ram
26. Sh. Leela Dutt son of Sh. Tulsi Ram, all resident of vill. Garkhal Gaon, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.
27. Smt. Veero wife of late Sh. Sayia Ram, resident of Vill. Banog (near Datyar), Tehsil Kasauli.
28. (a) Sh. Hari Om son of late Sh. Rama Nand, (b) Shri Mohan Dutt son of Sh. Rama Nand, all resident of vill. Banog (near Datyar) Tehsil Kasauli.

29. Sh. Jai Kumar son of late Sh. Sant Ram, resident of vill. Banog (Datyar), Tehsil Kasauli.
30. Sh. Sant Ram son of Sh. Devi Ram
31. Sh. Jagdish Kumar son of Sh. Devi Ram, all resident of vill. Nandoh, Tehsil Kasauli
32. (a) Sh. Uma Ram son of late Shri Kanhya, (b) Sh. Parkash son of late Sh. Kanhya, (c) Sh. Dhani Singh son of late Sh. Kanhya, all resident of vill. Nandoh, Tehsil Kasauli.
33. (a) Sh. Beli Ram son of late Sh. Dilya @ Dila Ram, (b) Sh. Tula Ram son of late Sh. Dilya @ Dila Ram, all resident of vill. Nandoh, Tehsil Kasauli.
34. Sh. Dharam Chand son of Shri Asha Ram
35. Sh. Sunder Lal son of Sh. Asha Ram
36. Sh. Nand lal son of Sh. Asha Ram, all residents of vill. Nandoh, Tehsil Kasauli
37. Shri Jiwan Singh son of Sh. Paras Ram, resident of vill. Nandoh, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh. .. Respondents

Application under section 123 of H. P. Land Revenue Act for partition of land comprised on Khata/Khatauni No. 27/54, 27/55 and 27/56 Kita 20, area measuring 10-07 bighas situated at Mauza Garkhal, Pargana Lachhrang, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

PROCLAMATION

Sh. Mahender Dutt son of Sh. Gauri Shankar, resident of Village and P. O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application for the partition of joint land comprised in Khata/Khatauni No. 27/54, 27/55 and 27/56, Kita 20, area measuring 10-07 bighas situated at mauza Garkhal, Pargana Lachharang, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

2. Whereas in the above mentioned case of partition the respondent No. 1(i) to (v), 3 to 6, 8, 9, 11(a), 12(a), 12(b), 13(a), 13(b), 14, 16 (b), 18(a), 18(b), 18(c) 18(d), 27, 31, 32(a), 32(b), 32(c), 37 were issued summons from this court so many time but service of summons have not been effected upon them through ordinary process. However by this proclamation they are hereby informed to be present before this court on 2nd day of September, 2011 at 10 A. M. to represent their case themselves or through their duly authorised agent failing which they will be proceeded ex parte.

Given under my hand and seal of the court this 29th day of July, 2011.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 1st Grade,
Kasauli, District Solan (H. P.).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 26 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0-वि0-अधिक मांगे/1-42/2011.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) (2011 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 26 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
 सचिव,
 हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2007-2008 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2011 है ।

2. **हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए ₹ 5,44,93,94,499 की ओर राशि प्राधिकृत करना.**—हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग ₹ 5,44,93,94,499 (₹ पांच सौ चवालीस करोड़, तिरानवे लाख, चौरानवे हजार, चार सौ निन्यानवे) है, वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोग के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी।

3. **विनियोग.**—इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोग के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 2007-2008 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत ₹	संचित निधि पर प्रभारित ₹	कुल ₹
1	2	3	4	5
01	विधान सभा (राजस्व)	45,70,194	—	45,70,194
02	राज्यपाल तथा मंत्री परिषद् (राजस्व)	—	8,75,841	8,75,841
03	न्यायिक प्रशासन (राजस्व)	—	34,99,208	34,99,208
04	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	1,30,54,936	—	1,30,54,936
05	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व)	32,26,29,295	—	32,26,29,295
06	आबकारी तथा कराधान (राजस्व)	59,64,517	—	59,64,517
07	पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	7,88,35,732	—	7,88,35,732
08	शिक्षा (पूँजीगत)	4,71,97,588	—	4,71,97,588
09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व)	31,23,73,281	—	31,23,73,281
10	लोक निर्माण, सड़कें, पुल तथा भवन (राजस्व)	1,26,38,21,810	—	1,26,38,21,810
	(पूँजीगत)	4,12,89,534	—	4,12,89,534
12	बागवानी (राजस्व)	1,04,98,038	—	1,04,98,038
13	सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता (राजस्व)	2,75,91,61,210	—	2,75,91,61,210
14	पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य (राजस्व)	7,75,73,108	—	7,75,73,108
	(पूँजीगत)	1,00,109	—	1,00,109
15	योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप योजना (पूँजीगत)	8,92,03,882	—	8,92,03,882
16	वानिकी एवं वन्य प्राणी (राजस्व)	80,93,732	—	80,93,732
18	उद्योग, खनन तथा आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व)	85,83,428	—	85,83,428
22	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति (पूँजीगत)	65,78,683	—	65,78,683

1	2	3 ₹	4 ₹	5 ₹
25	सड़क तथा जल परिवहन (राजस्व)	12,20,382	—	12,20,382
27	श्रम रोजगार तथा प्रशिक्षण (राजस्व)	1,96,522	—	1,96,522
31	जनजातीय विकास (राजस्व)	34,48,81,031	60	34,48,81,091
	(पूँजीगत)	4,91,92,378	—	4,91,92,378
	जोड़ (राजस्व)	5,21,14,57,216	43,75,109	5,21,58,32,325
	(पूँजीगत)	23,35,62,174	—	23,35,62,174
	सकल जोड़	5,44,50,19,390	43,75,109	5,44,93,94,499

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख अगस्त, 2011

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(वित्त विभाग नस्ति संख्या: फिन-ए-ए (4)-1/2008-पार्ट-1)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

Bill No. 15 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorization of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 2007-2008 in excess of the amount authorized or granted for those Services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2011.

2. Authorization of a further sum of ₹ 5,44,93,94,499 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial Year 2007-2008.—From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of ₹ 5,44,93,94,499 (₹ Five hundred forty four crores, ninety three lakhs, ninety four thousand, four hundred ninety nine) shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 2007-2008 in excess of the amount authorized or granted for those services and for that year.

3. Appropriation.—The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 2007-2008.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		Total
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	
1	2		₹	₹	₹
3	4	5			
01	Vidhan Sabha	(Revenue)	45,70,194	—	45,70,194
02	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	—	8,75,841	8,75,841
03	Administration of Justice	(Revenue)	—	34,99,208	34,99,208
04	General Administration	(Revenue)	1,30,54,936	—	1,30,54,936
05	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	32,26,29,295	—	32,26,29,295
06	Excise and Taxation	(Revenue)	59,64,517	—	59,64,517
07	Police and Allied Organisations	(Revenue)	7,88,35,732	—	7,88,35,732
08	Education	(Capital)	4,71,97,588	—	4,71,97,588
09	Health and Family Welfare	(Revenue)	31,23,73,281	—	31,23,73,281
10	Public Works—Roads, Bridges and Buildings	(Revenue) (Capital)	1,26,38,21,810 4,12,89,534	— —	1,26,38,21,810 4,12,89,534
12	Horticulture	(Revenue)	1,04,98,038	—	1,04,98,038
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue)	2,75,91,61,210	—	2,75,91,61,210
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue) (Capital)	7,75,73,108 1,00,109	— —	7,75,73,108 1,00,109
15	Planning and Backward Area Sub-Plan	(Capital)	8,92,03,882	—	8,92,03,882
16	Forest and Wildlife	(Revenue)	80,93,732	—	80,93,732
18	Industries, Minerals, Supplies and Information Technology	(Revenue)	85,83,428	—	85,83,428
22	Food and Civil Supplies	(Capital)	65,78,683	—	65,78,683
25	Road and Water Transport	(Revenue)	12,20,382	—	12,20,382
27	Labour Employment and Training	(Revenue)	1,96,522	—	1,96,522

1	2	3	4	5
		₹	₹	₹
31	Tribal Development	(Revenue) (Capital)	34,48,81,031 4,91,92,378	60 —
				34,48,81,091 4,91,92,378
	Total	(Revenue)	5,21,14,57,216	43,75,109
		(Capital)	23,35,62,174	—
				5,21,58,32,325
	Grand Total		5,44,50,19,390	43,75,109
				5,44,93,94,499

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 2007-2008.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
the August, 2011.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin-A-A (4)-1/2008-Part-I]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 2011, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 26 अगस्त, 2011

संख्या पी.बी.डब्ल्यू (बी) एफ (5)170/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव हारचक्कियां, उप-तहसील हारचक्कियां जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्तियाँ कर सकता है।

विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है० में)
कांगड़ा	हारचक्कियां	हारचक्कियां	98 / 2 / 1	0-00-48
			195 / 1	0-00-12
			196 / 1	0-00-25
			226 / 1	0-00-38
			229 / 1	0-00-48
			229 / 2	0-00-62
			252 / 1	0-00-56
			254 / 1	0-00-20
			255 / 1	0-00-24
			256 / 1	0-00-27
			257 / 1	0-00-24
			274 / 1	0-00-36
			276	0-01-02
			615 / 1	0-00-51
			616 / 1	0-00-36
			617 / 1	0-00-80
			895 / 705 / 1 / 1	0-00-28
			896 / 705 / 1 / 1	0-00-30
			900 / 893 / 705 / 1	0-00-11
			901 / 893 / 705 / 1	0-00-12
			902 / 893 / 705 / 1	0-00-08
			903 / 893 / 705 / 1	0-00-02
			904 / 893 / 705 / 1	0-00-24
कुल जोड			किता-23	0-08-04

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

(Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(6)-11/95, dated 11th August, 2011 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department.

No.FDS-A (6)-11/95

Dated, Shimla-2, 11.08.2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Bricks(Control)Act,1969(Act No. 29 of 1969) and all other powers enabling him in this behalf the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the Himachal Pradesh Bricks(Control)Order,1970,namely:-

1. Short title.

- (1) This order may be called the Himachal Pradesh Bricks (Control)(Amendment)Order,2011.
- (2) It shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Clause-4

In the Himachal Pradesh Bricks (Control) Order, 1970, in Clause 4, sub clause-(ii), the following shall be substituted, namely:-

“(ii) Subject to the general or special instructions notified by the State Government from time to time in this behalf a license may, if the site of kiln is not detrimental to the health and safety of the general public or to the crops, gardens or nurseries in close proximity there to, be granted or renewed by the District Magistrate. The kiln shall not be installed within a distance of 500 meters on both sides of the Electricity transmission lines having voltages of more than 220 KV. The distance shall be measured as the crow flies from the nearest transmission line.”

BY ORDER

PREM KUMAR

Principal Secretary (FCS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,

संख्या: एफ.डी.एस.ए.(6)-11/95

तारीख, शिमला-2

11.08.2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ईंट (नियंत्रण) अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्याक 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ब्रिक्स (कन्ट्रोल) आर्डर 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आर्डर बनाती है, अर्थात:-

1 **संक्षिप्त नाम ।**

- 1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ईंट (नियंत्रण) (संशोधन)आदेश, 2011 है ।
(2) यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

क्लाज 4 का संशोधन

- 2 हिमाचल ब्रिक्स (कन्ट्रोल) आर्डर 1970 के क्लोज 4 के सब क्लोज (ii)के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(ii) Subject to the general or special instructions notified by the State Government from time to time in this behalf a license may, if the site of kiln is not detrimental to the health and safety of the general public or to the crops, gardens or nurseries in close proximity there to, be granted or renewed by the District Magistrate. The kiln shall not be installed within a distance of 500 meters on both sides of the Electricity transmission lines having voltages of more than 220 KV. The distance shall be measured as the crow flies from the nearest transmission line.”

आदेश द्वारा,

प्रेम कुमार

प्रधान सचिव, स्वा०, ना० आ० एवं उप० मामले

(Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)-3/90-11, dated 26th July, 2011 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department.

No.FDS-A(3)-3/90-II

Dated, Shimla-2, 26th July, 2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles(Licensing & Control)Order,1981 read with S.O.654(E),dated 30.3.2011 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution(Department of Consumer Affairs),Government of India and published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated 30.3.2011,the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles(Licensing & Control)Order,1981,namely:-

1. **Short title and Commencement:-** (1) This Order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2011.
(2) It shall, except in the case of **Iodized Salt under PART-E** of the Schedule-1, come into force on the 1st day of April, 2011 and shall remain in force till 30th September, 2011 or till any order issued by the Government of India in this behalf, which ever is earlier.
2. **Amendmet of Schedule-1** In the **Himachal Pradesh Trade Articles(Licensing And Control) Order, 1981**, for **Schedule-1** the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-1

(See clause-2)

PART-A(FOODGRAINS)

1. Rice
2. Paddy.

PART-B(PULSES)

Pulses.

PART-C(OILSEEDS)

1. Edible Oil seeds.

PART-D(Edible Oils)

1. Edible Oils.

PART-E(OTHER ARTICLES)

1. Sugar.
2. Iodized Salt.

BY ORDER

PREM KUMAR

Principal Secretary (FCS&CA)to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

संख्या: एफ.डी.एस.ए.(3)-3/90-11

तारीख, शिमला-2 26.07.2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण(उपभोक्ता मामले, विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0संख्या 654(ई) तारीख 30.03.2011 के साथ पठित और भारत के राजपत्र में तारीख 30.03.2011 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :-

- | | | |
|------------------------|---|---|
| संक्षिप्त नाम और आरम्भ | 1 | (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) संशोधन आर्डर, 2011 है । |
| | | (2) यह शडयूल -1 के भाग-ई के अर्न्तगत आयोडाइज्ड साल्ट (आयोडीन नमक) के मामले के सिवाए, अप्रैल, 2011 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा और 30सितम्बर, 2011 तक या इस निमित्त भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त रहेगा । |

शडयूल-1 का संशोधन

2

हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 में शडयूल -1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

शडयूल-1**(खण्ड-2 देखें)****पार्ट-ए (फूडग्रेन्स) (खाद्यान्न)**

1. राईस (चावल)
2. पैडी (धान)

पार्ट-बी (पल्सेज) (दालें)

पल्सेज (दालें)

पार्ट-सी(आयल सीडज)(तिलहन)

एडिबल आयल सीडज (खाद्य तिलहन)

पार्ट-डी एडिबल आयलज (खाद्य तेल)

एडिबल आयलज (खाद्य तेल)

पार्ट-ई (अदर आर्टिकलज) अन्य वस्तुएं

- 1 शूगर (चीनी)
- 2 आयोडाइज्ड साल्ट (आयोडीन युक्त नमक)

आदेश द्वारा,

प्रेम कुमार

प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0एवं उप0मामले

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय के एस०ओ ० संख्या 3249 (ई) तारीख 18.12. 2009 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1 | (1).इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमैडमेंट आर्डर, 2010 है । |
| | | (2) यह तुरन्त प्रव्रत होगा और यह 30.09.2010 तक या इस निमित्त भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रव्रत रहेगा । |
| शडयूल-1 का संशोधन | 2 | हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल -1 में भाग-ई अदर आटिकलज (अन्य वस्तुएं) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थात:- |

“शूगर” (चीनी)।

आदेश द्वारा,

अजिल खाची

सचिव, खा०, जा० आ० एवं उप० मामले
हिमाचल प्रदेश सरकार,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,

संख्या: एफ.डी.एस.ए.(3)3/90.11

दिनांक, शिमला-2

16.7.2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले, विभाग) मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एस०ओ० संख्या 654(ई) तारीख 30.03.2011 के साथ पठित और भारत के राजपत्र, में तारीख 30.03.2011 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश

में पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) आदेश जी०एस०आर०-800 तारीख 9 जून, 1978 और उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग) आदेश एस०ओ० 681(ई) और 682 (ई) तारीख 30 नवम्बर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के आदेश संख्या एफ०डी०एस०-ए० (3) 8/ 2002 तारीख 3-02-2004 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ

1.इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2008 है ।

खण्ड 8 का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियामन) आदेश, 2008 (जिसे इस में इसके पश्चात् 'उक्त आदेश' कहा गया है) के उप खण्ड 2 में निम्नलिखित रखा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में उप खण्ड 1 के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रभाव डालें बिना, निरांत्रक, उसकी अधिकारिता के भीतर, इस आदेश के खण्ड 3 के उप खण्ड (5) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति को पूर्णतया या किसी भाग को समपहत कर सकेगा या थोक विक्रेता / उचित मूल्य की दुकान का धारक जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का "अपयोजन" यदि कोई किया गया हो, से नियंत्रित मूल्य तथा खुले बाजार में प्रचलित दर के हिसाब से तुलनात्मक (अन्तर) मूल्य की राशि के दोगुने के हिसाब से वसूल कर सकेगा और तदोपरि प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान का धारक जिसे इस प्रकार की वसूली का आदेश दिया हो, तुरन्त उक्त रकम को जमा करेगा:

परन्तु जहां खण्ड 16 के अधीन प्राधिकृत थोक विक्रेता / उचित मूल्य की दुकान के धारक को प्रतिभूति जमा करने से छूट दी गई है, सम्बन्ध अधिकारी उस थोक / परचुन विक्रेता को भी उक्त दर्शाई गई सजा कर सकेगा :

परन्तु यह और कि उप खण्ड (1) और उप खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, निरांत्रक, सम्बन्ध पक्ष को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा:

परन्तु यह और कि जहां प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक के विरुद्ध जांच लम्बित है और प्राधिकार के निलम्बित करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है, सम्बन्ध प्राधिकारी का समाधान होने पर, प्राधिकार को 6 मास से अनाधिक अवधि के लिए निलम्बित करेगा:'

3. उक्त आदेश में, खण्ड 15 के बाद, निम्नलिखित खण्ड 15-अ अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात -

'निदेशक को उक्त आदेश के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अतिरिक्त 'निरांत्रक' की शक्तियां विद्यमान हैं।'

आदेश द्वारा,

बी. के. अग्रवाल,
सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं

Comparative Chart showing the existing and proposed provisions of amendments alongwith remarks in H.P. Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003

S.No.	clause	Existing provisions	Proposed provisions	Remarks, if any
1	Amendment of clause 2.(u) Explanation I	Explanation- 1. In Urban areas the consumer card shall be issued by the District Inspector or Inspector of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department or any officer authorized by the Controller.	Explanation-I :- "In urban areas the consumer Card shall be issued by the Secretary/Executive Officer/Asstt. Commissioner of Urban Local Bodies viz Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayats, as the case may be, in their respective jurisdiction and countersigned by the president/chairperson/mayor of the concerned local bodies (in case of elected Urban Local Bodies) and Inspector, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs in cantonment Board area in their respective jurisdiction and , if the Urban Local Bodies is defunct the consumer cards shall be issued by the officer/official of Food,Civil Supplies & Consumer Affairs Department authorized for the purpose by the concerned "Controller."	To empower urban local bodies on the lines of rural local bodies; to decentralize powers in consonance with 74 th constitution amendment.
2	Amendment of clause 2.(u) Explanation 2	Explanation- 2. In Rural areas the consumer card shall be issued by the Pradhan Gram Panchayat in their respective jurisdiction and if there is no Panchayat Pradhan and the Panchayat is defunct, the consumer card shall be issued by any official / officer authorized for the purpose by the respective Controller of the District.	Explanation-2 "In rural areas the consumer cards shall be issued by the Secretary/Gram Panchayat of the concerned Gram Panchayat and counter signed by the Pradhan of the concerned Gram Panchayat in their respective jurisdiction and if the Panchayat is defunct,The Consumer cards shall be issued by the Officers/ Officials of Food,Civil Supplies & Consumer Affairs Department authorized for the purpose by the concerned "Controller	To fix accountability of the Issuing authorities.
	Amendment of last proviso of clause 8(2)	Provided further that where an enquiry is pending against authorized wholesaler or fair price shop holder, and it is considered necessary to suspend the authorization, the authority concerned, on satisfaction, shall suspend the authorization for the period not exceeding six months."	In clause 8 of the said order ,in sub clause(2)in the the last proviso ,the following proviso shall be added ,namely:- "Provided further that the suspension of authorization may exceed six months if the matter is pending in the Court".	

	Amendment of proviso of clause 10(2)	<p>The specified authority may before issuing a consumer card in Form-G make or cause to be made such enquiry, as he may deem fit, for verification of the information furnished by the applicant.</p> <p>“Provided that no consumer card may be issued unless the information furnished in Form ‘F’ by the applicant has been verified, by the Secretary of the Panchayat concerned on the basis of entries recorded in Pariwar Register in rural areas and; by the ward Member or Secretary or Executive Officer of the local body or Inspector, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs within their respective jurisdiction in Urban area, or; by the Head of Office/Controlling Officer in case of the employees of the Government/ Semi-Government / Public Undertakings.</p>	<p>In clause 10 of the said order , in sub clause(2),-</p> <p>(a) for the word “may” appearing in the first line, the word “shall” be substituted;</p> <p>(b) the word “he” appearing in the second line, shall be deleted;</p> <p>(c) after the word “applicant” appearing in the third line, the following shall be inserted namely:-</p> <p>“especially where the applicant and other members listed in Form-F submitted by him/her are physically residing at the address mentioned in the said “Form” and</p> <p>(d) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:-</p> <p>“Provided that no consumer card shall be issued unless the information furnished by the applicant in Form F has been verified by the Secretary/Panchayat Sahayak of the Panchayat concerned on the basis of entries recorded in Parivar Register in Rural Areas and by the Ward Member or Secretary or Executive Officer of the local body within their respective jurisdiction or by any officer/official authorized by the concerned Controller from time to time”.</p>	For the proper verification of the applicant on the basis of the record and to ensure subsidized rations are made available to people actually residing in the area, to also minimize chances of ghost ration cards.
5.	Amendment of clause 10(5)	<p>If a consumer card has been lost, defaced ,damaged, the holder thereof may apply to the specified authority for duplicate consumer card and such application shall be accompanied by a fee as specified in sub clause (3). The specified authority may , after making such enquiry as he deems fit , issue a duplicate consumer card.</p>	<p>(b) in sub clause(5), for the word “a fee” the words “double of the fee” shall be substituted;</p>	To avoid the misuse of Government stationery.

6.	Amendment of clause 10(15)	The specified authority in relation to rural area shall obtain printed application and consumer cards forms from the controller on payment of the cost of such forms as specified in this clause. Out of the fee of the consumer card so realized 20% shall be reimbursed to the Panchayats as service charges for preparation of the consumer card.	(C) for sub clause (15), the following shall be substituted namely:- “(15) The Specified authority in relation to rural area or urban area shall obtain printed application and consumer card Forms from the Controller on payment of the cost of such Forms as specified in this clause. Out of the fee of the consumer cards so realized 50% shall be reimbursed to the concerned Urban Local Bodies or Panchayats, as the case may be, as service charges for preparation of the consumer cards:	To empower urban local bodies and to uncenturise the local bodies as well as augment their resources.
7	Substitution of form F	At the S. No. 11 of the Form new sub Serial No. D included 1. Signature of the enquiry officer with seal (Inspector FCS&CA/ Gram Panchayat Vikas Adhikari 2. Signature of card preparing officer/ official	“In Form “F” in serial No.11, after clause(c), the following shall be inserted namely:- “(d) All the members mentioned at serial No.10 are physically residing with me and their names are not entered in any consumer cards anywhere in India, and (b) In the column “FOR OFFICIAL USE ONLY” for the existing two seals, the following seals shall be substituted namely:- 1. Signature of enquiry officer with seal (specified authority) and 2. Signature of preparing officer/official (specified authority)	Under taking for the proper verification of the card holder and only the stamp and seal of the authority has been changed. Remaining main proforma is as it is.
8	Substitution of Form-G	1. Signature of the Panchayat President /Distribution Officer with seal 2. Signature with seal of Panchayat President or specified authority	In form G, for seals “Signature of Panchayat President/ Distribution Officer with seal,” and “Signature with seal of Panchayat President or Specified Authority” the following seals respectively shall be substituted namely:- “Signature of the Specified Authority with seal /Counter –signing authority with seal and signature with seal of Specified Authority.”	The main object of proposed amendment is to take legal action against the Specified issuing Authority if the consumer card is found bogus and only the stamp and seal of the authority has been changed. The main proforma is as it is.

No. FDS-A(03)01/2007-I

Dated, Shimla-171002, the 10th June, 2010

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under Section 5(1) and (2) and 19 of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005) is pleased to designate the following officers as Appellate Authority, Public Information Officer in Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department at the Government level with immediate effect in public interest:-

Sr.No,	Designation and Address of the officer	Telephone No.	Designated as
1.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary(FCS&CA) to the Government of HP	0177-2621902	Appellate Authority
2.	Special/Additional/Joint/Deputy/Under Secretary(FCS&CA) to the Government of HP.	0177-2625346	Public Information Officer

By Order

Additional Chief Secretary (FCS&CA) to the
Government of Himachal Pradesh.

(Authoritative English text of this Department notification No. FDS-A(3)-1/99, dated 4th June, 2010 as required under article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department.

No. FDS-A (3)-1/99

Dated, 4th June, 2010.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act 10 of 1955) read with Government of India Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Order published under GSR No. 800, dated 9th June, 1978 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend the Himachal Pradesh, Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 notified by this Department No. FDS-A(3)15/80, Dated, Shimla-171002, the 14th April, 1981 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated the 23rd May, 1981.

1. Short title, extent and commencement.

- (1) This Order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2010.
- (2) It extends to the whole of State of Himachal Pradesh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of clause(3)

In the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, in clause(3), in sub-clause (1) the word "for sale" appearing after the word "storage" shall be deleted.

By Order,

HARINDER HIRA
Additional Chief Secretary (FCS&CA)

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Deptt.

No.FDS-A(3)2/2004

Dated, Shimla-2, 27.3.2008.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act 10 of 1955) reads with the Government of India in the late Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Order, GSR-800 dated 9th June, 1978 and Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) Order S.O. 681 (E), and 682 (E) dated 30th November, 1974, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order to amend the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 notified vide this Department Notification No. FDS-A (3) 8/2002 dated the 28-11-2003 and published in the extra ordinary Rajpatra of Himachal Pradesh Govt. dated 03-02-2004, namely:-

Short title & Commencement

1. This order may be called The Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) (First Amendment) Order, 2008.

Amendment of clause 8

2. In the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2008, (hereinafter referred to as the said order), in clause 8, for sub-clause (2) the following shall be substituted, namely:-

“Without prejudice to any action that may be taken under sub-clause(1) in respect of contravention of any of the provisions of this order, the controller, within his jurisdiction, may forfeit the whole or part of the security deposited under sub-clause (5) of clause 3 of this order or, recover double the amount as differential cost between the Controlled price and the market price of diverted specified Articles, if any, and thereupon the authorized wholesaler or the Fair Price Shop holder, shall forth with deposit an amount so as to make the deficiency good in the amount:

Provided that where an authorized whole saler or fair price shop holder is exempted from deposit of the security under clause 16, the officer concerned, may also impose penalty as mentioned above to these wholesaler / fair price shop holder:

Provided further that before passing any Order under sub-clause (1) or sub-clause (2), the Controller shall give a reasonable opportunity of being heard to the party concerned:

Provided further that where an enquiry is pending against authorized wholesaler or fair price shop holder, and it is considered necessary to suspend the authorization, the authority concerned, on satisfaction, shall suspend the authorization for the period not exceeding six months.”

3. In the said order, after clause 15, the following clause shall be inserted as clause 15 –A, namely:-

“The Director shall have all the powers of the “Controller” in addition to the power specified in this order.”

By Order,

B.K. Aggarwal,
Secretary (FCS&CA) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

संख्या: एफ.डी.एस.ए.(3)2/2004

दिनांक, शिमला-2

27.3.2008

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अब भारत सरकार में पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) आदेश जी0एस0आर0-800 तारीख 9 जून, 1978 और उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग) आदेश एस0ओ0 681(ई) और 682 (ई) तारीख 30 नवम्बर, 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग के आदेश संख्या एफ0डी0एस0-ए0 (3) 8/ 2002 तारीख 3-02-2004 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2008 है ।

खण्ड 8 का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 2008 (जिसे इस में इसके पश्चात् 'उक्त आदेश' कहा गया है) के उप खण्ड 2 में निम्नलिखित रखा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में उप खण्ड 1 के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रभाव डालें बिना, नियंत्रक, उसकी अधिकारिता के भीतर, इस आदेश के खण्ड 3 के उप खण्ड (5) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति को पूर्णतया या किसी भाग को समपूत कर सकेगा या थोक विक्रेता / उचित मूल्य की दुकान का धारक जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का "अपयोजन" यदि कोई किया गया हो, से नियंत्रित मूल्य तथा खुले बाजार में प्रचलित दर के हिसाब से तुलनात्मक (अन्तर) मूल्य की राशि के दोगुने के हिसाब से वसूल कर सकेगा और तदोपरि प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान का धारक जिसे इस प्रकार की वसूली का आदेश दिया हो, तुरन्त उक्त रकम को जमा करेगा:

परन्तु जहां खण्ड 16 के अधीन प्राधिकृत थोक विक्रेता / उचित मूल्य की दुकान के धारक को प्रतिभूति जमा करने से छूट दी गई है, सम्बन्ध अधिकारी उस थोक / परचुन विक्रेता को भी उक्त दर्शाई गई सजा कर सकेगा :

परन्तु यह और कि उप खण्ड (1) और उप खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, नियंत्रक, सम्बन्ध पक्ष को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करेगा:

परन्तु यह और कि जहां प्राधिकृत थोक विक्रेता या उचित मूल्य की दुकान के धारक के विरुद्ध जांच लम्बित है और प्राधिकार के निलम्बित करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है, सम्बन्ध प्राधिकारी का समाधान होने पर, प्राधिकार को 6 मास से अनाधिक अवधि के लिए निलम्बित करेगा:'

3. उक्त आदेश में, खण्ड 15 के बाद, निम्नलिखित खण्ड 15-अ अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

“निदेशक को उक्त आदेश के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अतिरिक्त ‘नियंत्रक’ की शक्तियां विद्यमान हैं।”

आदेश द्वारा,

बी. के. अग्रवाल,
सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश सरकार,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,

संख्या: एफ.डी.एस.ए.(3)-2/2004

दिनांक, शिमला-2

02.3.2009

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत सरकार में पूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) आदेश जी0एस0आर0-800 तारीख 9 जून, 1978 और उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग) आदेश एस0ओ0 681(ई) और 682 (ई) तारीख 30 नवम्बर, 1974 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा (5) के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0डी0एस0-ए0 (3) 8/ 2002 तारीख 28-11-2003 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 3-2-2004 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु वितरण का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2009 है।

खण्ड 7 का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु वितरण का विनियमन) आदेश, 2003 (जिसे इस में इसके पश्चात् ‘उक्त आदेश’ कहा गया है) के खण्ड 7 में उप खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“उचित मूल्य की दुकान का धारक प्ररूप ‘घ’ में दैनिक विक्रय / स्टॉक रजिस्टर बनाये रखेगा और उपभोक्ता को विनिर्दिष्ट वस्तुएं वितरित किये जाने के प्रतीकस्वरूप, सरकार या निदेशक या सम्बद्ध नियंत्रक द्वारा विहित “कैश मेमो” भी जारी करेगा तथा **कैश मेमो पर उसके हस्ताक्षर करवायेगा”**।

प्ररूप-घ का प्रतिस्थापन

3. उक्त आदेश से संलग्न विद्यमान प्ररूप ‘घ’ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात्:-

प्ररूप-घ

(खण्ड 7 (4) देखें)

उचित मूल्य की दुकान के धारक द्वारा रखा जाने वाला दैनिक विक्रय स्टॉक रजिस्टर

तारीख	विनिर्दिष्ट वस्तुओं के नाम	आरम्भिक अतिशेष	प्राप्त की गई मात्रा	कुल (3+4)	विक्रय की गई मात्रा	अन्त अतिशेष	टिप्पणी, यदि कोई हो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

आदेश द्वारा,
हरिन्द्र हीरा,
अति0 मु0 सचिव।

(Authoritative English text of this Department Order No. FDS-A(3)2/2004 dated 2.3.2009 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Deptt.

No.FDS-A(3)2/2004

Dated, Shimla-2, 2.3.2009.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act 10 of 1955) the Government of India in the late Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) Order, GSR-800 dated 9th June, 1978 and Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) Order S.O. 681 (E), and 682 (E) dated 30th November, 1974, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order to amend the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003 notified vide this Department Notification No. FDS-A (3) 8/2002 dated the 28-11-2003 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh Extra ordinary dated 03-02-2004, namely:-

Short title & Commencement

1. This order may be called The Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) (Second Amendment) Order, 2009.

Amendment of clause 7

2. In the Himachal Pradesh Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 2003, (hereinafter referred to as the "said order"), in clause 7, for sub-clause (4) the following shall be substituted, namely:-

"The Fair Price Shop Holder shall maintain a daily sale/stock register in Form "D" and shall also issue a **"Cash Memo"** prescribed by the Government or the Director or the concerned Controller" to the consumer in token of having issue the Specified Articles and **obtain his signatures on the Cash Memo**".

Substitution of Form-D.

3. For the existing Form-"D" appended to the said order, the following shall be substituted, namely:-

FORM -"D"

{See clause No. 7(4)}

Daily sale/stock Register to be maintained by the Fair Price Shop Holder

(Figures in Quintals, Kilograms & Grams)

<u>Date</u>	<u>Name of Specified Articles</u>	<u>Opening Balance</u>	<u>Quantity received</u>	<u>Total (3+4)</u>	<u>Quantity sold</u>	<u>Closing balance</u>	<u>Remarks, If any</u>
<u>1.</u>	<u>2.</u>	<u>3.</u>	<u>4.</u>	<u>5.</u>	<u>6.</u>	<u>7.</u>	<u>8.</u>

By Order,

Harinder Hira,
Additional Chief Secretary (FCS&CA) to the
Govt. of Himachal Pradesh.